



सरगरा समाज की धर्मशाला के आसपास की जमीन समाज के लिए आरक्षित रखनी चाहिए

पिछली जमीन पर कोलोनीया काटकर भूमाफिया करोड़ों रुपए कमाई कर रहे हैं

वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर की मिलीभगत से अवैध कोलोनीया पनप रही है इनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए

2 हजार बिधा जमीन गोचर की भूमाफियाओं ने खा गए पटवारी हाथों नाम करवा दी अब 16 बिधा जमीन ही रखी है बडगाँव में गोचर

ग्रीन बेल्ट में मार्स्टर प्लान के विपरीत आवासीय योजना कैसे स्वीकृत हो गई

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज उपखंड क्षेत्र के कामबेश्वरजी महादेव मंदिर सड़क पर शहर के मास्टर प्लान शिवगंज सुमरपुर 2011-31 में ग्रीन बेल्ट में कॉलोनी काटी गई कैसे काटी कॉलोनी इसकी जांच होनी जरूरी है क्योंकि भूमाफियाओं ने धन देकर उल्टा सीधा काम तो किया पर इन्होंने यह नहीं सोचा कि इसके मुख्य सड़क पर हीरागढ़ सरगरा समाज की धर्मशाला है इस धर्मशाला में हर वर्ष बड़े-बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें आने वाले सेकड़ों लोगों को बड़ी समस्या होती है पर सरकारी अधिकारियों को यह पता नहीं कि यह पीछे वाली वह पास वाली जमीन सरकारी है तो इसमें कैसे कॉलोनी कट गई और प्लॉटों की रेट लाखों रुपए रख दी प्लाट बेचने चालू भी कर दिए इन भूमाफियाओं ने क्योंकि संतोष नार नामक कॉलोनी रखकर इस धर्मशाला का मुख्य द्वार पर अतिक्रमण कर दिया क्योंकि धर्मशाला के चारों तरफ नो नो मीटर साइड बैक भूमि पड़ी है वह कहां गई या तो हो सकता है इन भूमाफियाओं ने खीरीद ली या अधिकारियों पर दबाव देकर यह उल्टा काम करवा दिया क्योंकि यह बडगाँव क्षेत्र है इसमें तरमीम के नाम पर लाखों रुपए बटोरे गए यहां किसान दुखी हैं और भूमाफियाओं मजा कर रहे हैं लाखों रुपया लेकर किसी की जमीन किसी पर बताकर यह फौजीवाड़ा कर दिया अधिकारियों ने लाखों रुपए लिए होंगे फोकट करने जैसे एक भी अधिकारी नहीं है पर भूमाफिया की ?10 हजार रुपये विधा की जमीन का सीधा 10 लाख रुपया विधा में वह बंगले बनाकर आनंद करते हैं किसान बेचारे रो रहे हैं क्योंकि जमीन किसानों की गई है और यह भूमाफियाओं किसानों को बदाकर उनको पीछे के तरफ धकेला गया क्योंकि आगे जमीन किसानों की थी आपका नाम की मैं करवा दूंगा आप



इतना सामान पहुंचा देना सामान लेने में यहां के पटवारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इनके बीच में भी दलाल सक्रिय थे पैसा दलाल लेते थे और इनके घर पर पहुंचा देते थे यहां के कर्मचारियों ने बड़ी-बड़ी जमीन ले ली लड़ी-बड़ी गाड़ियां में वह बंगले बनाकर आनंद करते हैं किसान बेचारे रो रहे हैं क्योंकि जमीन किसानों की गई है और यह भूमाफियाओं किसानों को बदाकर उनको पीछे के तरफ धकेला गया तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है उनके जमीन पर दूसरे बैठकर बड़ी खेती कर रहे हैं किसान चुपचाप जमीन को देखकर वापस जा रहा है क्योंकि उनके हक की जमीन वह प्रशासन की धमकी के आगे किसान छुप हो गया बडगाँव तरमीम अभी 2022-23 में हुई है और इन्होंने सालों तक नहीं होना इसका फायदा इन भूमाफियाओं ने उठाया है जब तरमीम हुई तब अधिकारी कौन-कौन थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और कहां पर 2000 बिधा और कहां 16 बिधा जमीन आ गई 2000 बिधा के लिए खेतीवाड़ी करनी चाहिए।

वहां पर तरमीम की हो गई और गोचर भूमि अपने नाम की करवा कर किसानों के साथ बड़ा भीतरी घात किया क्योंकि शिवगंज क्षेत्र के आसपास गांव में बडगाँव गांव में बडगाँव गांव में तरमीम के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है किसान परेशान है कहीं ने न्यायालय करवाई जाए पर प्रशासन नहीं वापस करवाई जाए पर वापस नहीं सुन रहा है क्योंकि सब धन के आगे नतमस्तक है अगर ऐसा ही चला रहा तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है उनकी जमीन किसानों के नाम पर बैठकर बड़ी खेती कर रहे हैं तो किसान चुपचाप जमीन को देखकर वापस जा रहा है क्योंकि उनके हक की जमीन वह प्रशासन की धमकी के आगे किसान छुप हो गया बडगाँव तरमीम अभी 2022-23 में हुई है और इन्होंने सालों तक नहीं होना इसका फायदा इन भूमाफियाओं ने उठाया है जब तरमीम हुई तब अधिकारी कौन-कौन थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और कहां पर 2000 बिधा और कहां 16 बिधा जमीन आ गई 2000 बिधा के लिए खेतीवाड़ी करनी चाहिए।

उन्हें वापस अपनी जमीन पर बैठाना ही उचित रहेगा नहीं तो किसान आंदोलन की राह पर आ जाएगा वह प्रशासन को गोचर की भूमि वापस गोशाला के नाम पर खुली रखनी चाहिए 2000 बिधा जमीन से 16 बिधा जमीन कैसे हो गई यह हजारों इसीलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करवाने में काई कसर नहीं छोड़ी इसीलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करवाने की राह पर आ जाएगा वह भ्रष्टाचार करवाने के गरीबों को वापस अपनी जमीन दिलानी चाहिए वह भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाकर गौमाताजी के लिए खेतीवाड़ी करनी चाहिए।

भीलवाड़ा में कांग्रेसी बोले: नगर परिषद भूमाफियाओं के दबाव में पट्टे जारी करने में भ्रष्टाचार हुआ; सभापति को सौंपा ज्ञापन

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे देकर भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस ने आज नगर परिषद के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया और मुख्य सचिव के नाम नगर परिषद के सभापति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी सख्ती से अधिकारियों को दबाव देकर भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर पट्टे जारी कर देता है। वहीं जिन लोगों को पट्टे की आवश्यकता है और जिन्होंने पिछले 1 साल से पट्टे के लिए फाइलें लगा रखी हैं, उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में नगर परिषद ने प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर कृष्णा नगर



800 पट्टे की फाइल एक साल से मैंडिंग पड़ी है। लेकिन उन्हें अभी तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा मिली भगत और बेइमानी पूर्वक मनमाने तरीके से अपने चहेतों को पट्टे दिए जा रहे हैं, जो जल्लरतमंद लोग हैं उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा जाच की जाए। हमारा प्रदर्शन एक दिन में खल नहीं होगा, आगे जल्लरत पट्टी तो हम आंदोलन करेंगे। धरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम नगर परिषद सभापति को ज्ञापन दिया और कबड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिष्पक धर्मदंड कुमार परीक, महामंत्री महेश सोनी, जीपी खटीक, राजकुमार प्रजापत, योगेश सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी दिया। नगर परिषद में लगभग

ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा नकली तेल सीज़: खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऑयल इंडस्ट्रीज में मार्यादा छापा, कोटा समेत बाहर होता सप्लाई

द पुलिस पोस्ट

कोटा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अधियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा में बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने रानपुर में शिवम एडिल ऑयल इंडस्ट्रीज में छापा मारा और करीब साढ़े 7 हजार लीटर तेल कपड़ा है। यहां पर तेल को प्रोसेस करके अलग-अलग ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके से निवार्वा, राजस्थान, पोस्टमैन समेत अन्य ब्रांड के नकली तेलार किए गए तेल के पीपे, पैकिंग, समेत अन्य सामग्री जब की है। इसकी खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया- कुछ समय पहले विभाग की टीम ने यहां से सैंपल लिए थे, जो जाच में सबस्टैंडर्ड के मिले। यहां ब्रांडेड के नाम से मिलावटी तेल बेचने की सूचना मिल रही थी। जिस पर आज टीम के साथ मौके पर आए और ब्रांड के नाम पर बाजार के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कच्चा माल खरीद कर ब्रांड में पैकिंग

पंकज ओझा ने बताया निवार्वा, बीकानर, कोटा, बूदी सहित हाड़ौती सम्भाग में दुकानदारों को 100 रुपए लीटर में सप्लाई करता था। उन्हें अपने यहां 5-6 ब्रांड से पैक किया जा रहा था। पिर ब्रांडेड बताकर कोटा और बाहर सप्लाई किया जा रहा था। शुल्काती में सामने आया कि ये माल कोटा, बूदी सहित हाड़ौती सम्भाग में दुकानदारों को 100 रुपए लीटर में सप्लाई करता था।

मौत बांटते असुरक्षित कोचिंग सेंटर, पीजी और हाँस्टल

दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत-हादसे ने समूचे राष्ट्र को दुःखी एवं आहत किया है, यह हादसा नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, लापरवाही एवं लोभ की पराकाशा है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर दोषग्रस्त कोचिंग प्रणाली और व्यवस्था की जड़ों में समाया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिर तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिर तार किया गया जो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। इस दुःखद एवं पीड़ादायक घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। जिसकी कीमत निदोषों को अपनी जान गंवा का चुकानी पड़ रही है। निः त ही देशभर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए कोचिंग सेंटर डैथ सेंटर बन चुके हैं। कोचिंग सेंटरों का कारोबार शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। छात्रों को सुनहरी भविष्य का सपना दिखा कर मौत बांटी जा रही है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिंगवतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद ऐसे हो चुकी मेटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। प्रश्न है कि सेंटर के मालिक को तो गिर तार कर लिया लेकिन ऐसी घटनाओं के दोषी अधिकारी क्यों नहीं गिर तार होते?

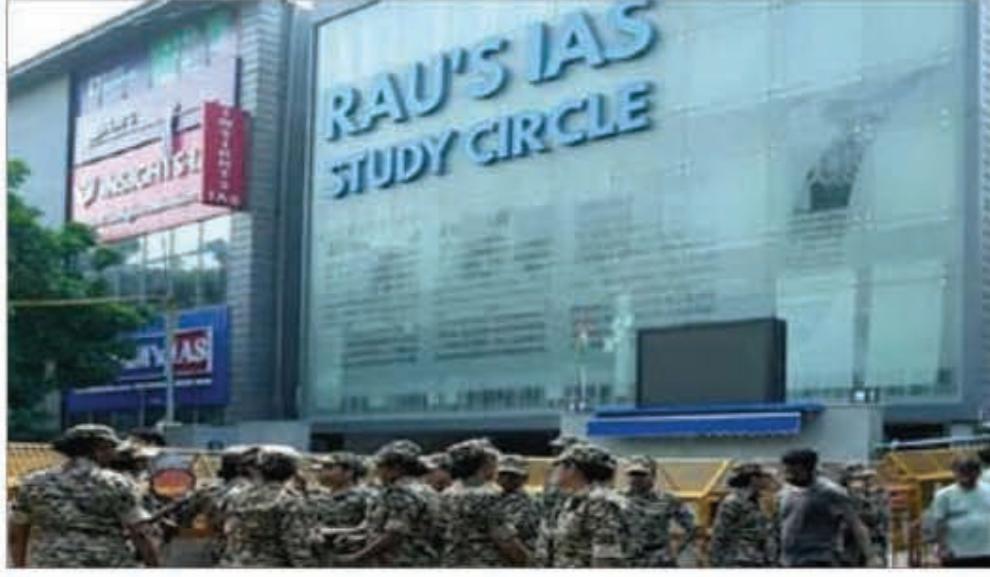
शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली के ओल्ड रोजेन्ड नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डोल्विन, तान्य सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खड़ा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आइएएस की तैयारी कर रहा था और वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव ने अभी एक महीना पहले ही इस कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जहां 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। हादसे के वर्ते 35 छात्र मौजूद थे। चंद मिनटों में ही बेसमेंट में पानी भर गया। सिर्फ इसी सेंटर में नहीं, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बार्नाई गई है। जिसके गेट बायोमैट्रिक आईडी से खुलते हैं, जैसे ही बारिश होती है, बिजली चली जाती है, उसके बाद बेसमेंट से निकलना बिना बायोमैट्रिक आईडीटिप्फिकेशन के मुश्किल होता है।

बात हम नया भारत एवं
विकसित भारत की करते
हैं, लेकिन हमारी
व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं
बनी हैं और हम
अनियंत्रित एवं असुरक्षित
विकास करते जा रहे हैं।
मुंबई हो, दिल्ली हो,
चैन्नई या बैंगलुरु या ऐसे
ही अन्य बड़े शहर -हर
कहीं अनियोजित विकास
और शहरी निर्माण संबंधी
नियम-कानूनों के खुले
उल्लंघन के घलते आए
दिन दुर्घटनाएं होती रहती
हैं। स्थिति यह है कि
सरकारी भवनों तक में
सुरक्षा के उपायों की
अनदेखी होती है।



ડા. આરોંગ વાણીષ

बात हम नया भारत एवं
विकसित भारत की करते
हैं, लेकिन हमारी
व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं
बनी हैं और हम
अनियोक्ति एवं असुरक्षित
विकास करते जा रहे हैं।
मुंबई हो, दिल्ली हो,
चैन्नई या बैंगलुरु या ऐसे
ही अन्य बड़े शहर -हर
कहीं अनियोजित विकास
और शहरी निर्माण संबंधी
नियम-कानूनों के खुले
उल्लंघन के घलते आए
दिन दुर्घटनाएं होती रहती
हैं। स्थिति यह है कि
सरकारी भवनों तक में
सुरक्षा के उपायों की
अनदेखी होती है।



ऐसी स्थिति में हादसे और मौत की संभावना बढ़ जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर के न सिर्फ कोचिंग सेंटर बल्कि पीजी और हॉस्टल की असुरक्षित हालत भी मौत लिये किसी भी क्षण बड़े हादसे की संभावना के साथ खड़ी है। जहां इस कदर अवैध निर्माण है कि कभी भी दूसरा या दोबारा हादसा हो सकता है। इसलिये ऐसे हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला।

विडम्बनापूर्ण है ऐसे जलभराव एवं आगजनी के हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भायपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूट का सहारा लेती है। राजधानी में रह-रह कर एक के बाद एक हो रहे हादसों के बावजूद दिल्ली-सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक एम्यूजमेंट पार्क के अंदर गेमिंग जौन में लगी आग की लपटें हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बच्चों के एक प्राइवेट हॉस्टिल में आग लगना और अब कोचिंग सेंटर में तीन होनहार एवं देश के भविष्य बच्चों का दर्दनाक तरीके से डूबकर मर जाना-नि त रूप से ये हादसे प्रशासनिक लापरवाही की उपज हैं, यही कारण है कि सिस्टम में खामियों और ऐसी आपदाओं को रोकने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की निंदा भी व्यापक स्तर की जा रही है। यह याद रखने योग्य है कि नियमित अंतराल पर मानवीय जिम्मेदारी वाले पेपलू की अनदेखी से ऐसी गंभीर घटनाएं होने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और

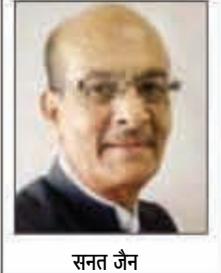
लापरवाही कम होती नहीं दिख रही है। इन त्रासद हादसों ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। परिवार वालों ने और छात्रों ने स्वर्णिम भविष्य के सपने संजो कर और लाखों की फीस देकर कोचिंग शुरू की होगी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। छात्रों की मौत को महज हादसा नहीं माना जा सकता, यह एक तरह से निर्मम हत्या है और हत्यारा है हमारा सिस्टम। हादसे से आक्रोशित छात्रों का कहना है कि वे 10-12 दिन से दिल्ली नगर निगम से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई कारबाई जाए लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हादसे तभी होते हैं जब नियमों और कानूनों को ताक पर रखा जाता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलते ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। जलतभारव क्यों और कैसे हुआ, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन इन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को उसके मालिकों ने मौत का कुआं बना रखा था। आखिर क्या बजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वर्णी पर स्याह हनन होता है। हर दुर्घटना में गलती भ्रष्ट आददी यानी अधिकारी एवं व्यवसायी की ही होती है, लेकिन

दुर्धटना होने के बाद ही उन पर कार्रवाई क्यों होती है? सरकार पहले क्यों नहीं जागती? वैसे तो बेसमेंट में कोचिंग सेन्टर या लाइब्रेरी चलाना गैर-कानूनी है, इस घटना के सन्दर्भ जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुपस्थिति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। जलभराव के कारण पानी जब बेसमेंट में खुसा तब लाइब्रेरी में 30-35 ब्रात्रि थे। यह तो गरीमत रही कि तीन अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे-तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जलभराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सूध नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एमसीडी न एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ-साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है।

बात हम नया भारत एवं विकसित भारत की करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं बनी है और हम अनियंत्रित एवं असुरक्षित विकास करते जा रहे हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, चैन्सी या बैंगलुरु या ऐसे ही अन्य बड़े शहर -हर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। दिल्ली के इनकम टैक्स भवन में आग से एक अधिकारी की जान हाल में गयी। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक हैं या निरोपों को परेशानी करने के लिये हैं। औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े-बड़े दावे करने और उन्हें सवारने की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाप्रस्त एवं असुरक्षित हैं। हर हादसे पर सियासत होती है लेकिन कोचिंग सेंटर माफिया इतना ताकवर है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा क्यों है यह सब जानते हैं।

संपादकीय

538 लोकसभा सीटों पर पढ़े वोट और गिने गए वोटों पर अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह



सनत जैन

लो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफर्म (एडीआर) ने सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। 362 लोकसभा की सीटों पर मतदाताओं द्वारा डाले गए और गिने गए वोटों में 5,54,598 वोटों का अंतर है। मतगणना कम वोटों की की गई है। जबकि जीतने वाले प्रत्याशी और दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। इससे जीत-हार प्रभावित हुई है। लोकसभा की 176 लोकसभा सीटों पर वोट कम पड़े और 35093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। 538 सीटों पर कुल वोटों का अंतर 5,89,691 पाया गया है। इस संस्था के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदान का डाटा जारी करने में भी परिदिशित नहीं बरती गई है। चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के आंकड़े काफी विलंब से जारी किए गए। प्रारंभिक मतदान और अंतिम मतदान के परिणामों में 5 करोड़ से अधिक वोटों का अंतर पाया गया है। अभी भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना के आंकड़े मतदान केंद्र के हिसाब से जारी नहीं किए गए हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना को लेकर संदेह बना हुआ है। जबकि यह जानकारी पूर्व में चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही थी। एडीआर ने 79 लोकसभा सीटों का एक अलग विश्लेषण जारी किया है। जिसमें मतदान कम होने की जानकारी दी गई थी। जब मतगणना हुई, उसमें करोड़ों वोट ज्यादा गिने गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव पचार के दौरान और मतदान

के बीच में आदर्श आचार संहिता की जो शिकायतें कर्म गई थीं, उन पर भी चुनाव अयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा शिकायतों का भेदभाव पूर्ण ढंग से निपटारा करने का आरोप लगा है। इसको लेकर भी चुनाव अयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार पक्षपाता और सदेह व्यक्त किया जा रहा है। एसोसिएशन फॉन्डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक ऐसी संस्था है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायाधीश, वकील और पत्रकार भी शामिल हैं। यह संस्था पिछले कई वर्षों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का डाटा इक और करती आ रही है। उसका विश्लेषण करती है, और समय-समय पर वह डाटा सार्वजनिक पोर्टल पर जारी करती है। इस संस्था की बड़ी विश्वसनीयता मतदाताओं, मीडिया और संस्थाओं के बीच में बनी हुई है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध डाटा के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए गड़बड़ियों को उजागर करती है। समय-समय पर इस संस्था द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं के माध्यम से लोकतात्रिक व्यवस्था सुठंड करने की कोशिश की गई है। मतदाताओं के लोकतात्रिक अधिकार सुरक्षित रह सकें, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करती है। ५ वर्ष पहले भी इस संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के कारण डिटेल में जाकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में ईंवीएम मशीन बीवीपेट मशीन, बीवीपेट से निकली हुई मतदान पर्चियों की गिनती, माइक्रोकंट्रोल यूनिट इत्यादि के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चुनाव के दौरान जो गड़बड़िया थी उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, सुनवाई के बाद जे आदेश पारित किए थे, उसका पालन भी चुनाव अयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत नहीं किया गया। चुनाव अयन्त्रों की नियक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट

ने जो फैसला दिया था। उसको बदलते हुए सरकार ने एक नया कानून बनाया। जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तीन सदस्यों की कमेटी ने चुनाव के ठीक पहले तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। यथा नियुक्ति भी विवादों में है। नए कानून को चुनौती देवाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोकसभा वे चुनाव हो चुके हैं। परिणाम भी घोषित हो चुके हैं लोकसभा के सदस्यों ने शपथ भी ले ली है। सरकार का गठन भी हो गया है। ऐसी स्थिति में ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफर्म द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है संगठन ने चुनाव आयोग से भी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देने के स्थान पर छुपाया जा रहा है। इससे भी सदैव बढ़ रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के जनविधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदान की जानकारी शाम को 7 बजे और दूसरे दिन दोपहर 11 बजे तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितन मतदान हुआ है। उसको मतदान केंद्र के हिसाब से जारी कर देती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव आयोग द्वारा जो प्रारंभिक मतदान की जानकारी दी गई थी। उसके कई दिनों बाद मतदान के जो आंकड़े जारी किए गए, उनमें करोड़ों वोटों का अंतर है निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अभी तक मतदान केंद्र वे मतगणना का आंकड़ा मतदान केंद्रों के हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा पोर्टल पर नहीं डाला गया है। एवं निः त समय पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव याचिका हाईकोर्ट में दायर करनी पड़ती है। इससे तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, निर्वाचन क्षेत्र का दूसरे नंबर का उम्मीदवार यदि मतगणना से सहमति नहीं है। वह राशि भरकर 45 दिन के अंदर जांच कर मांग कर सकता है। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई नियम नहीं बनाए हैं। जिन पराजित उम्मीदवारों ने आवेदन लगाए थे, उस पर भी को कर्वाई अभी तक चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है भारतीय लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद मतदान पर ही ग्रस्त गई है। निर्वाचित परिनिधियों द्वारा बहम

के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। मतदाताओं से मिले हुए इस अधिकार से केंद्र एवं राज्य सरकार का गठन होता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें जनता के लिए कानून बनाती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसी के अनुसार काम करती हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसको निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है। चुनाव आयोग, चुनाव की निष्पक्षता, पारिदर्शिता और सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर मिलें। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलें। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की गई है। यदि मतदाताओं को चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं होगा? चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करेगा, तो लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयुक्त को नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी बिना डर और भय के सवाल कर सके। बिना किसी दबाव में आए काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कमेटी बनाई थी, उसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिष्ठकों को शामिल किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ना मानते हुए, जो कानून बनाया। उसमें तीन सदस्यों की कमेटी में दो सदस्य सरकार के और एक विपक्ष का रखा गया। जिसके कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर, मतदान और मतगणना पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, जो प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर खड़े हुए हैं। उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करके, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। लोकतंत्र तथा संविधान मजबूत हो। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन आज भी सबसे सशक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान केंद्रीय चुनाव आयोग से भी अपेक्षा की जाती है।

भूखमरी : खत्म करने की चुनौती

मजबूर है। ये जानकारी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2024' नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), यूनिसेफ, विभ खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज दुनिया की एक तिहाई आवादी ऐसी है, जो पोषण युक्त आहार खरीदने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए ज़ृद्धाना पड़ रहा है। इनमें 86.4 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। वास्तविकता में देखें तो पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण के स्तर 2008-2009 के स्तर पर पहुंच चुका है हालांकि देखा जाए तो ये स्थिति तब है जब सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक किसी को खाली पेट न सोने देने की बात कही गई थी। मतलब की इन छह वर्षों में दुनिया को एक लंबा सफर तय करना है। रिपोर्ट में ये चतावनी भी दी गई है कि अगर

मौजूदा हालात इसी तरह से जारी रही, तो 2030 तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इनमें से आधे अफ्रीका में होंगे साफ है, दुनियाभर में तमाम प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असामनता और कुपोषण जैसे मुद्दे पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यूं तो इंसान पांच दशक पहले ही चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों के चांद रोटी में नजर आता है। ताजा रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में भूखमरी के संबंधा घटने की बजाए तेजी से बढ़ रही है। साफ है भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय किया जाना बार्क्स है। ये कैसी विडंबना है एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझ कर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खानातक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूझ और मर रहे हैं। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है। गौं करने वाली बात ये है कि दुनिया में बढ़ती संपन्नता वे साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने

की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। अगर इस बाबार्दी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, खाद्यान्न की क्षति और बाबार्दी न केवल संसाधनों के कुप्रवंधन का मुद्दा है बल्कि ये बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्पविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं तथा विकास के संर्द्धे में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको ये बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। ये कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

बिना जानकारी के सभापति और पार्षदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस डीबी से नहीं हुआ नगर परिषद के पक्ष में फैसला

राजीव नगर सम्बन्धित जानकारी सैन के पास मिलेगी झूठी नहीं बनाए

द पुलिस पोस्ट



खोलना का निर्णय हुआ 2017 सिंगल बेंच से नगर परिषद के पक्ष में निर्णय होने के उस समय के सभापति ताराराम माली जगदीश सैन महावीर भाई रामलाल परिहार इत्यादि लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद मोटेशन नगर परिषद के नाम हुआ नगर परिषद के नाम मोटेशन खोलना के बाद सभापति ताराराम माली ने अधिकारी

अभियंता दिलीप माथुर जो कार्यवाहक आयुक्त भी थे कार्यवाहक आयुक्त माथुर साहब व नगर परिषद की अतिक्रमण रोधी दस्ता राजीव नगर भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे ताकि अतिक्रमण हटाकर भूमि की पैमाइश कर लॉटरी प्रक्रिया से भूमिहीन लोगों को आवासीय भुखण्ड आवंटन किया जा सके जैसे ही राजीव नगर

आवासीय योजना के अतिक्रमण कतार्हों को हटाने के लिए नगर परिषद के आयुक्त और टीम मोके पर पहुंची उसी समय पूर्व विधायक साहब पहुंच कर अतिक्रमण कतार्हों के पुनर्वास की मांग कर अतिक्रमण हटाने नहीं दिये बाद में राजीव नगर के सड़क किनारे के भुखण्डों की निलामी कर करोड़ों राजस्व अर्जित कर दिया

माननीय हाईकोर्ट से रिपोर्ट
1251/08 नगर परिषद देखते
पै निर्णय के खिलाफ तेजाराम
व्र गिरीश ने डीबी हाईकोर्ट देखते
र दी
गिरीश का उक्त भूमि संबंधी
लिकाना हक हकूक नहीं २
जाराम जी ने नगरपालिका
लेकर बेची भूमि को पुनः

अपने परिवार के सदस्यों के बजाय जैन ट्रान्सपोर्ट सिरोही में हमाली का कार्य करने वाले छगनलाल के हक में तेजाराम जी ने जीते जी 2010 में वसीयत कर दी तेजाराम जी के मृत्यु बाद 2010 में ही तेजाराम जी द्वारा छगनलाल के नाम की गई वसीयत उप पंजीयक कार्यालय सिरोही में वसीयत रजिस्टर्ड हुई जिसमें तेजाराम जी के संमूर्ण परिवार के सदस्यों द्वारा दस रुपए के तरस्वीक शुदा शपथपत्र छगनलाल के हक में सहमति पत्र दिए और हस्ताक्षर किए सहमति पत्र देने वालों में गिरीश भी शामिल था अपील में गिरीश गैरकानूनी रूप से गया 2017 में नगर परिषद के पक्ष में सिंगल बैंच से नगर परिषद के पक्ष में निर्णय बाद डीबी में गिरीश द्वारा अपील की गिरीश एवं नगर परिषद द्वारा हाईकोर्ट में वसीयतनामा छुपाया गया जिसके कारण डीबी में गिरीश की अपील पर निर्णय लिया हुआ कि 175 की कार्यवाही जारी रहेगी और उक्त भूमि नगर परिषद के नाम बिलानाम आवंटन होती है तो तेजाराम जी परिवार को चार प्लॉट 1800 वर्ग फिट के दिये जाये जो नगर परिषद के पक्ष में फैसला नहीं होने के कारण नगर परिषद सिरोही गिरीश की अपील पर आये निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गये और डीबी के फैसले पर स्टे लिया यानी 2017 में नगर परिषद के पक्ष में आये फैसला यथावत है वर्तमान में नगर परिषद सिरोही की राजीव नगर आवासीय योजना की पैरवी करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के ध्यान में लाया जाए की डीबी में गिरीश की अपील पर हुये निर्णय में गिरीश द्वारा वसीयतनामा को छुपाकर गुमराह किया गया है राजीव नगर आवासीय योजना की पुरी डिटेल अथवा जानकारी समझना कोई इच्छुक हैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र पुरी अथवा पूर्व पार्षद जगदीश सैन से समझ सकते हैं कुछ लोग सोसल मीडिया एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी अधूरी जानकारी साझा कर रहे हैं।

राजीव नगर खुर्दबुर्द मामला

पहले आवेदन खारिज का प्रस्ताव जनता में किरकिरी बाढ़ झापन

आयुक्त के विरुद्ध कारवाई करनी चाहिए जैल भेजना चाहिए

द पुलिस पोस्ट



सिरोही, राजीव नगर आवासीय योजना में वर्ष 89 के दशक में आवासीय भुखण्ड प्राप्त करने के भूमिहीन लोगों द्वारा जमा करवाएं फार्म के बाद नगरपालिका ने कई बार आवेदन कतार्हों से भूमिहीन के शपथपत्र प्राप्त किए गए वर्ष संयम लौटा के सानिध्य में सभापति मैद्र मेवाड़ा के नेतृत्व में आयोजित बोर्ड बैठक में राजीव नगर आवासीय योजना में भूमिहीन आवेदन कतार्हों के एकाएक फार्म निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया यानी भूमाफिया को सुगमता से भूमि हड्डपने का मार्ग सुलभ करा दिया यह सब कुछ नगर परिषद सिरोही के कांग्रेस बोर्ड में हुआ इन्हीं सभापति मैद्र मेवाड़ा के कांग्रेस बोर्ड के राज में राजीव नगर समेत चार पांच बिलानाम सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मिलिभगत कर आनलाइन आर टी जी एस से अपने कोष में पैसा जमा करवाया यह सब किसके इशारे पर हुआ अब चूंकि राजीव नगर आवासीय योजना को खुर्दबुर्द करने का मामला आम जनता की नजरों में आ चुका और किरकिरी हो रही है तो पाकसाफ बताने के लिए पूर्व कार्यवाहक आयुक्त को निलंबित करने और कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सभापति और कांग्रेस पार्षद ज्ञापन और प्रेस कांफ्रेंस कर अपने को इमानदार पारदर्शी दिखाने का दिखाव किया जा

तेजाराम जी द्वारा बेची भूमि की 2010 में गैरकानूनी तेजाराम जी ने वसीयत छगनलाल के नाम कर दी और तेजाराम जी के मृत्यु बाद वसीयत रजिस्टर्ड छगनलाल के नाम हो गई उसके बाद छगनलाल ने अपने नाम मोटेशन खोलना के तहसील में आवेदन कर दिया दूसरी और 2017 में सिंगल बेंच नगर परिषद के पक्ष में फैसला आने के बाद उस फैसले के खिलाफ डीबी में गिरीश गया लेकिन नगर परिषद सिरोही के सभापति आयुक्त और सदस्यों के संज्ञान में आने के बावजूद हाईकोर्ट डीबी में गिरीश की अपील पर छगनलाल के हक में की गई वसीयत और उस वसीयत में गिरीश समेत तेजाराम जी के परिवर्जनों द्वारा छगनलाल के हक में दिये शपथपत्र व वसीयत की कोपी मेरे द्वारा नगर परिषद सिरोही को फोटो कोपी देने के बावजूद हाईकोर्ट डीबी के संज्ञान में किसके दबाव में नहीं लाया गया राजीव नगर आवासीय योजना में आयकर विभाग आयकर कोलानी स्कूल के लिए नगरपालिका ने भूमि दे दी भवन बन गए नगर परिषद ने सिमेंट सङ्क बना दी व्यवसायिक प्लोटो की निलामी कर दी सभी जगह बहुमंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन गये इसका विरोध कभी किसी ने नहीं किया ना कभी कोई व्यक्ति कोर्ट से स्टे लेकर आया जो कुछ खेला खेला गया व बेनामी रिश्वत की कमाई के लिए और शायद जनता को तो समझ में आ गया होगा की पूर्व कार्यवाहक आयुक्त द्वारा लिखे पत्र के पीछे असली किरदार कौन है।

**कोणे के भूखंड मे खड़ा खोदकर छोड दिया गया
बारिश के पानी भरने से होगा
बड़ा हादशा जनहानी होगी**

**पालिका प्रशासन अंधा
बनकर क्यू बैठा है
कारवाई क्यू नहीं
करते**

द पुलस पास्ट



मूर्खिय कानार का ह इसमें सुरक्षा दावार नहा बनाना से
इस सड़क होकर रोजाना सैकड़े गाड़ियाँ जाती है कोई
भी बारिश में बड़े बच्चे पिरे तो जनहानि हो सकती है
वयोंकि फिर बचाया नहीं जा सकता अगर अभी कार्रवाई
कर दे तो अंडरग्राउंड खोदने से रोका जा सकता है और
अंडरग्राउंड को छोड़ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग व्यवस्था
की जानी चाहिए जिससे दलिली जैसा हादशा नहीं हो
जाए सरकारी नाली को तोड़कर गंदा पानी रोका गया है
और सड़कों पर फैल रहा है बीमारियाँ फैल रही है नाली
तोड़ने का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए व अवैध
अतिक्रमण को तुरंत हटावे

कॉल कर प्रेमी को बुलाया, लाठीःडंडों से पीटकर किया मर्डरःसबूत
मिटाकर हॉस्पिटल में रख आए डेडबोडी; प्रेमिका समेत 6 गिरफ्तार

द पुलिस पोस्ट



बाढ़मेर। प्रेमिका ने कॉल कर बुलाया तो प्रेमी बस में स्वावर होकर प्रेमिका के गांव पहुंच गया। रात 1.30 घर में एंट्री की तो प्रेमिका के पूरे परिवार ने उसे घेर कर दबोच लिया। रातभर प्रेमी को टॉर्चर किया गया। पेशाब पिलाया गया। टॉर्चर से युवक की मौत हो गई तो डेडबॉडी हॉस्पिटल में पटक कर फरार हो गए। मंगलवार को प्रेमिका समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला बालोतरा जिले के सिनधरी थाना इलाके के गांव कोशलू का है। शनिवार सुबह 6.30 बजे पुलिस ने डेडबॉडी बरामद की थी। मंगलवार को मामले का खुलासा कर दिया गया। सिनधरी थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया-बाढ़मेर की नागाणा जांगुओं की ढाणी ग्राम पंचायत के गांव सकेनपिणों की टाणी में उड़ने वाला सगाराम

गया। परिजनों ने उसे एक-दो बार पकड़ लिया। समझाया और मगाराम के घरवालों को उलाहना देकर छोड़ दिया। इसके बाद भी मगाराम ने जेठी से मिलना बंद नहीं किया। जेठी के परिवार वालों ने घर में उत्तर्ष कैमरे लगवा दिए। पुलिस के मुताबिक-शुक्रवार शाम 6 बजे जेठी ने मगाराम को फोन किया और रात में घर आने को कहा। मगाराम अपने गांव मुकेनाणियों की ढाणी में था। यहां से कोशलू की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। उसने घरवालों को बताया कि वह ऑयल वेलपेड के काम से जा रहा है। वह शाम को गांव से बस पकड़ कर रात तक प्रेमिका के गांव कोशलू पहुंच गया। इसके बाद देर रात 1 बजे के करीब वह जेठी के घर में घुसा। इस दौरान लड़की के परिजनों ने मगाराम को पकड़कर बंधक बना लिया। आरोप है कि जेठी के परिवार के 10-12 सदस्यों ने मगाराम को जारी तारी नंदों से तीव्र चाप लगी।

यह आरोप भी है कि उसे घंटे मारपीट के दौरान जब तो आरोपी डेढ़बॉडी को फूला और बॉडी वही छोड़कर फूला मगाराम के चाचा खरथाराम थाने में जेरी समेत 9 लोग मामला दर्ज करवाया था। पिता और एक भाई है। पुत्री सुबह 6.30 बजे सूचना कोशलू गांव में एक युवक कोशलू गांव पहुंची, घटना किया तो वहाँ किसी संधर्षण नहीं मिले। आरोपियों ने सचला कि युवक को पिक्का हॉस्पिटल ले जाया गया थिए। अंतिम तिथि तीव्र रूप से

राब पिलाया गया। कई गाराम ने दम तोड़ दिया और धरी हॉस्पिटल ले गए। इस संबंध में शनिवार को सिणधरी के खिलाफ मर्डर का गाराम के घर में माता-पिता के मुताबिक- शनिवार ली थी कि कुछ लोग ने पीट रहे हैं। पुलिस एल का मौका मुआयना कर पीट या खून के सबूत मिटा दिए थे। यह पता नहीं में रखकर सिणधरी को बदाम तांडे से पटा जड़ा कि डेडबॉली को यहां छोड़कर आरोपी भाग गए हैं। इसी कल्प के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने आरोपियों की तलाश की। सिणधरी पुलिस ने प्रेमिका जेरी (20), उसकी मां चूनी देवी (40), पिता चौथाराम (45) पुत्र रुपाराम, ताजाराम (32) पुत्र मेघाराम, खेराजाराम (26) पुत्र रेखाराम, मानाराम (45) पुत्र हिमताराम को गिरफ्तार कर लिया। सभी लोग सिणधरी थाना इलाके के सड़ा झुंड गांव के रहने वाले हैं। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसपी कुंदन कंवरिया के निर्देशन में एसपी धर्मेंद्र कुमार यादव, सिवाना डीएसपी नीरज शर्मा, बायतु डीएसपी गुमानाराम, बायतु और सिवाना के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी व साइबर टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम, एमओबी टीम ने मौके पर पहुंचकर सातवं तक रहा।



आरयू में अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी

अन्न त्यागा, इलाज नहीं कराने पर अड़ा; छात्र संघ हुनाव कराने की मांग

जयपुर। शुभम तीन मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड्डियां पर है।

छात्र नेता ने कहा- मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के एलान पर हो गया है। छात्रसंघ चुनाव पर से शुरू करने समेत तीन सौ मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम की तबीयत बिगड़ी है। वहीं छात्र नेता मांग नहीं माने जाने तक अन्न त्यागने और इलाज नहीं लेने की जिद पर है।

छात्र नेता शुभम रेखा ने कहा- 18 जुलाई को यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक एलाकेशन के माध्यम से ये पूछा था कि पिछले सालों में छात्रसंघ चुनाव के नाम पर ली जा रही पूछा का यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या किया है। इसके साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बत्त ली जाने वाली काशन मरी अब

तक किन्तु स्टॉडेंस को उनकी डिग्री समाप्त होने पर वापस दी गई। यूनिवर्सिटी की ओर से इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, जिसके बिलाफ़ कोट में एफआईआर दर्ज की।

छात्र नेता ने कहा- मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड्डियां पर है। लेकर तीनों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के सुनाविक इस वायरस से कोई बच्चा संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति और उसके घर के जानवर तक का सैंपल लिया जाएगा। इसके साथ ही जिस एरिया में केस मिलेंगे उस घर के आस-पास के 50 घरों में सर्वे कर संदर्भों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदर्शक डॉ. रवि प्रकाश माथूर की ओर से जारी गाइड लाइन में बताया- राजस्थान में डॉकरपुर में एक केस मिला है। गुजरात में इसके कई केस सामने आ चुके हैं। इसमें मौत होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए सभी जिलों के सीएम-एचओ, मैडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी पीयूओ को निर्देश दिया है कि जो गाइड लाइन जारी की है, उसका पालना करते हुए बीमारी को नियंत्रित करने का काम करें।

ये हैं तीन मांगें

जिन सालों में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे, तब तब के रूप पर स्टॉडेंस का वापस की जाएगा।

कांसांग मनी के रूपये और पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

इस बार जो छात्रसंघ चुनाव शुल्क आम छात्रों से वसूला गया है, उसकी एवज में छात्रसंघ चुनाव का आयोजन कराया जाए।

महिला की गला घोटकर हत्या का आरोप

जयपुर।

जयपुर में विवाहिता के फंदा लगाकर सुझाड़ मामले में नया मोड़ आ गया है। विवाहिता के चर्चे भाई ने पति का सवाल लिया और कार्य के बाद विवाहिता की देवर से शादी हड्डी थी। पूर्व मांगों से बाताचारी को प्रार्थित करते विवाहिता की देवर से शादी हो गई। परिवार की शकायत पर कोटियावदा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआई सुवालाला ने बताया- तुगं निवासी कृष्ण कुमार (31) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी चर्ची बहाने करता गुजर (26) की शादी मनमोहनपुरा निवासी विनोद गुजर से हड्डी थी। कुछ समय पहले कविता की पति विवाहित की रोड एक्सीट में मौत हो गई। सामाजिक रिटि विवाह से कविता के देवर विवाहित की नाता करवाकर चुड़ी पहन दी थी। उसके बाद विवाहित की पत्नी बनकर कविता विवाहित की दूसरी लड़की से हड्डी सगाई को परिवारवालों ने खत्म कर दिया था। परिवार की सहायता से देवर-भोजाई का नाता राजवाहन दिया था। विवाहिता कविता के भाई कृष्ण कुमार का आरोप है कि कविता के पत्नी बनने के बाद भी विवाहित की दूसरी लड़की से हड्डी सगाई को परिवारवालों ने खत्म कर दिया था। परिवार की सहायता से देवर-भोजाई का आरोप है कि कविता के भाई कृष्ण कुमार का आरोप है कि कविता के पत्नी बनने के बाद भी विवाहित की दूसरी लड़की से हड्डी सगाई को परिवारवालों ने खत्म कर दिया था। एसआई दिनेश चन्द्र ने बताया- दलपतपुरा चाक्सू निवासी विनोद सिंह नरका (27) की चाक्सू सभी मंडी के पास बाईसा राजपूती परिधान की दुकान है। पिछले कई दिनों से दो आदमी और एक औरत दुकान पर आकर कपड़ों की खरीददारी कर रहे थे। दुकान पर आने के चलते उनसे जान-पठावान हो गई।

नकली गोल्ड देकर व्यापारी से 2 लाख रुपए ठगे
तीन बदमाशों में एक महिला भी शामिल, पिता की खाराब तबीयत का बनाया था बहाना
जयपुर।

जयपुर में नकली गोल्ड देकर व्यापारी से 2 लाख रुपए ठगे का बदमाशों ने कस्टमर बनकर कपड़ा व्यापारी से जान-पठावान बढ़ावी थी। इसके बाद नकली गहने गिरवी रखकर रुपए लेकर भाग गए। चाक्सू थाने में व्यापारी से

एसआई दिनेश चन्द्र ने बताया- दलपतपुरा चाक्सू निवासी विनोद सिंह नरका (27) की चाक्सू सभी मंडी के पास बाईसा राजपूती परिधान की दुकान है। पिछले कई दिनों से दो आदमी और एक औरत दुकान पर आकर कपड़ों की खरीददारी कर रहे थे। दुकान पर आने के चलते उनसे जान-पठावान हो गई।

कोटा में 20 कोच की वंदे भारत का ट्रॉयल

160 किमी की रफ्तार से दौड़ी, यात्रियों के बजन के बराबर भार रखकर की टेस्टिंग

कोटा।

कोटा मंडल में इन दिनों वंदे भारत रैक का ट्रॉयल (परीक्षण) किया जा रहा है। आज 20 रैक का ट्रॉयल लाखों से गुडला के बीच तीन बार किया गया। ट्रॉयल के दौरान वंदे भारत को दिल्ली-मुंबई अप लाइन पर गुडला से लाखों के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे

की रफ्तार से दौड़ाया गया।

कपलर और पहियों में लगे कड़ी सेंसर से डाटा इक्ट्रो किया गया। इस रैक का ट्रॉयल अराडीएस्ए के संयुक्त देशक (परीक्षण) एस के यात्रव के निर्देशन में किया जा रहा है। कोटा के ट्रैफिक निरीक्षक अराविद पाठक व लोको निरीक्षक नाहर सिंह ने लखनऊ टीम

तक किया गया। इसके बाद भारत रैक के ट्रैफिक सिस्टम के लिए डायल किया गया।

आरयू में अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी

तक किया गया। इसके बाद भारत रैक के ट्रैफिक सिस्टम के लिए डायल किया गया।

जयपुर। शुभम तीन मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड्डियां पर है। लेकर तीनों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के सुनाविक इस वायरस से कोई बच्चा संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति और उसके घर के जानवर तक का सैंपल लिया जाएगा। इसके साथ ही जिस एरिया में केस मिलेंगे उस घर के आस-पास के 50 घरों में सर्वे कर संदर्भों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदर्शक डॉ. रवि प्रकाश माथूर की ओर से जारी गाइड लाइन में बताया- राजस्थान में डॉकरपुर में एक केस मिला है। गुजरात में इसके कई केस के सामने आ चुके हैं। इसमें मौत होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए सभी जिलों के सीएम-एचओ, मैडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी पीयूओ को निर्देश दिया है कि जो गाइड लाइन जारी की है, उसका पालना करते हुए बीमारी को नियंत्रित करने का काम करें।

ये हैं तीन मांगें

जिन सालों में छात्रसंघ चुनाव के एलान पर हो गया। ये किसी तरीके से वसूला गया है। छात्रसंघ चुनाव पर तीन मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड्डियां पर है। लेकर तीनों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के सुनाविक इस वायरस से कोई बच्चा संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति और उसके घर के जानवर तक का सैंपल लिया जाएगा। इसके साथ ही जिस एरिया में केस मिलेंगे उस घर के आस-पास के 50 घरों में सर्वे कर संदर्भों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदर्शक डॉ. रवि प्रकाश माथूर की ओर से जारी गाइड लाइन में बताया- डॉकरपुर में एक केस मिला है। गुजरात में इसके कई केस के सामने आ चुके हैं। इसमें मौत होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए सभी जिलों के सीएम-एचओ, मैडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी पीयूओ को निर्देश दिया है कि जो गाइड लाइन जारी की है, उसका पालना करते हुए बीमारी को नियंत्रित करने का काम करें।

ये हैं तीन मांगें

जिन सालों में छात्रसंघ चुनाव के एलान पर हो गया। ये किसी तरीके से वसूला गया है। छात्रसंघ चुनाव पर तीन मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड्डियां पर है। लेकर तीनों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के सुनाविक इस वायरस से कोई बच्चा संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति और उसके घर के जानवर तक का सैंपल लिया जाएगा। इसके साथ ही जिस एरिया में केस मिलेंगे उस घर के आस-पास के 50 घरों में सर्वे कर संदर्भों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदर्शक डॉ. रवि प्रकाश माथूर की ओर से जारी गाइड लाइन में बताया- डॉकरपुर में एक केस मिला है। गुजरात में इसके कई केस के सामने आ चुके हैं। इसमें मौत होने का खतरा



थानेदारों से मंथली वसूली मामला तत्कालीन एसपी सहित 15 बरी

वकील ने एसीबी का प्री-प्लान क्राइम बताया, तत्कालीन एसपी बोले- गलत तथ्य पर केस किया था दर्ज

द पुलिस पोस्ट

अजमेर। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एसपी लोकेश सोनवाल सहित 9 बरी आई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। अजमेर भृष्टाचार निरोधक की डेजिनेटेड कोर्ट ने मामले में आज फैसला सुनाया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री-प्लान क्राइम बताया। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि ये गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी है वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट इडिशनल एसपी है।



एसपी आईपीएस राजेश मीणा ने कहा- गलत तथ्य के आधार पर बनाया, जिस्या और साक्ष्य विहीन केस दर्ज किया गया। शुरू से ही न्यायपालिका पर विश्वास था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

सभी 15 आरोपी बरी

मामला 2 जनवरी 2013 का है, जिसमें एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल जोधपुर जेन को भी आरोपी माना था। मामले सकारा है पराजित नहीं। रेडिशनल एसपी लोकेशन सोनवाल ने कहा-

साल 7 माह पुराना यह कोई सामान्य मुकदमा नहीं, बल्कि जाती वैमनस्यता का मुकदमा है। यह संविधान की ताकत है कि वक्त लगा लेकिन न्याय मिला।

किया था। एसीबी ने जांच के बाद आरोप-पत्र पेश किया था, जिसमें तत्कालीन एसपी लोकेश सोनवाल, तत्कालीन सीआई अशोक विश्नोई, रविंद्र यादव, बंशीताल, खन मोहम्मद, हनुमान सिंह, सुनील विश्वार्ण, जयपाल धारणिया, गोपाल लाल, प्रमोद स्वामी, संजय शर्मा, कुशल राम, रामदेव ठठेरा और हेमन्त जेन को भी आरोपी माना था। मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 30 जुलाई